AGPE THE ROYAL GONDWANA RESEARCH JOURNAL
OF HISTORY, SCIENCE, ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
ISSN (E): 2583-1348 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 04 | Issue 02 | February 2023 | www.agpegondwanajournal.co.in | Page No. 21-26

भारतीय लोकतंत्र में साम्प्रदायिक राजनीति एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. विजय सिंह

सहायक आचार्य - राजनीति विज्ञान
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
अलसीसर, झुंझुनू , राजस्थान

सारांश :

आधुनिक शासन प्रणाली में लोकतंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय शासन के रूप में विकसित हो चुका है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को यह गौरवान्वित दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्टतया पंथनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया है, 42 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है। भारत की स्वतंत्रता साम्प्रदायिक विभाजन के दशं के साथ प्राप्त हुई, जिससे देश में धर्मनिरपेक्षता के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी। परंतु भारतीय लोकतंत्र विकट परिस्थितियों के बावजूद निरंतर मजबूती से सुदृढता की ओर एक नया मुकाम हासिल करता रहा है। सदियों से जीओ और जीने दो तथा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना ने भारत को शांति और सोहार्द के रूप में विश्व पटल पर नामित किया है, इसी भावना को संविधान में भी स्थान दिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के द्वारा बोये गये साम्प्रदायिक बीज समय–समय पर अंकुरित होते रहे हैं। स्वतंत्र भारत में यद्यपि इस पर नियंत्रण करने के लिए कानूनी तरीकों को विशेष रूप से अपनाया गया परंतु राजनीतिक स्वार्थ के चलते साम्प्रदायिक मुद्दों को समय–समय पर हवा दी जाती रही है और वर्तमान में विशेष रूप से इसका दायरा बढता जा रहा हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। प्रजातंत्र में जाति धर्म की राजनीति को जब स्थान दिया जाने लगता हैं तो निश्चित रूप वह अपने मुल आदर्शो को खो देता है और साम्प्रदायिकता के ताण्डव को आमंत्रण मिल जाता हैं, जो किसी भी दृष्टि से स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व व विकास का परिचायक नही कहा जा सकता है।

शब्द कुंजी : साम्प्रदायिक, प्रजातंत्र, संविधान, पंथनिरपेक्ष, समानता, राजनीति

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
Dr. Vijay Singh Assistant Professor - Dept. of Political Science Govt. Girls College, Alsisar, Jhunjhunu, Rajasthan. Email: vijaysinghpols@gmail.com	

प्रस्तावना :

भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर हैं यहां विविध जाति, धर्म व सम्प्रदाय के लोग निवास करते है। ये भारतीय जनतंत्र की खुबसूरती है कि विविधताओं के बावजूद साम्प्रदायिक सोहार्द व समन्वय को बनाये रखने में प्रगति की ओर अनवरत बढता रहा है। अनेक धर्मों की संस्कृति में परस्पर समन्वय की भावना ने देश की जनता को परस्पर जोड़ने का काम किया हैं जिससे राष्ट्र मजबूती से विकास की ओर बढा है। स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्मों के अनुयायियों के परस्पर सहयोग ने इस देश के नागरिकों में भाइचारे को विशेष रूप से एकसूत्र में पिरोने का काम किया, परंतु अंग्रेजो की फूट डालो व राज करो की नीति ने भारतीय जनता को जाति धर्म के आधार पर बाँटने का विविध स्तर पर प्रयास किया जिससे एक दूसरे के विरूद्ध जहर घुलना स्वाभाविक ही था। हिन्दु मुस्लिम अग्रेजों के विरूद्ध संगठित होकर लड़े, परन्तु साम्प्रदायिक राजनीति की छदम् नीति के आगे मात खा गये, जिससे भारत दो भागों में साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित हुआ। भारत व पाक विभाजन से दोनों तरफ साम्प्रदायिक आग को हवा मिली और जिससे साम्प्रदायिक राजनीति का आगाज होना भी स्वाभाविक था। स्वतंत्र भारत में साम्प्रदायिक राजनीति की जड़े विरासत से ही जुड़ी हुई हैं, जिसे राजनीतिक दलों ने अपने निहित संकीर्ण स्वार्थ के लिए समय–समय पर हवा देने का काम किया है। जो कि लोकतांत्रिक शासन में अस्वीकार्य हैं गाँधी के शब्दों में ''धर्म एक निजी मामाला है, जिसकी राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।''[1] भारतीय संविधान में सभी धर्मो को समान दर्जा दिया गया है तथा जाति धर्म को राजनीति से दूर रखने की अपेक्षा की गई है। बी.जी. गोखले के अनुसार ''राजनीति से धर्म के अलग हो जाने से हिन्दू और मुसलमानों के पुराने विरोध फिर कभी उत्पन्न नहीं होगें।''[2] संविधान में धर्मनिरपेक्षता व समानता पर आधारित शासन व्यवस्था का प्रावधान किये जाने के बावजूद साम्प्रदायिक राजनीति को बल मिला हैं, जाति व धर्म के आधार पर अनेकों घटनाओं ने लोकतंत्र पर आघात किया है। वर्तमान भारतीय राजनीति का ये कड़वा सच साबित हो रहा हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा ही जाति व धर्म आधारित बनती जा रही हैं जो विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

शोध साहित्य समीक्षा :–

- ए. सूर्य प्रकाश – लोकतंत्र, राजनीति और धर्म – एक पत्रकार व लेखक के रूप में इस पुस्तक में भारतीय शासन व राजनीति का विश्लेषणत्मक विवेचन विभिन्न मुद्दों के सन्दर्भ किया गया हैं, विशेष रूप से साम्प्रदायिक राजनीति की यथा स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
- चौधरी डॉ. लाखा राम – भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास, 2019 – प्रस्तुत पुस्तक में लेखक के द्वारा भारतीय राजनीति में निर्वाचन सुधार की दिशा में आवश्यक प्रयास पर प्रकाश डालते हुऐ, राजनीतिक दलों द्वारा भ्रमित किये जाने वाले असंवैधानिक प्रयास भ्रष्टाचार, सामप्रदायिक विद्वेष आदि को उजागर किया है।
- आई.स्टेवन विलकिंसन – धार्मिक राजनीति और सांप्रदायिक हिंसा (भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दें), 2005 – अधोलिखित ग्रंथ में भारतीय राजनीति में सांम्प्रदायिकता की यथास्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ के लिए धार्मिक मुद्दों को सांमप्रदायिक रगं दिया जा रहा है। धर्म के आधार पर राजनीति का विस्तार भारत में एक गम्भीर समस्या के रूप में बढ रही है।

[1] महात्मा गाँधी, कलेक्टेड वर्क्स, जिल्द 76, पृ. 402
[2] बी.जी. गोखले – द मकिंग ऑफ द इण्डियन नेशन, पृ. 243

- वाजपेयी अमित – भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति, 2015 – उक्त ग्रंथ में भारतीय राजनीति में जाति व धर्म की भूमिका का विश्लेषण किया गया हैं। लेखक के द्वारा स्पष्ट किया गया हैं आधुनिकता के दौर में सामाजिक दृष्टि से जाति व धर्म के बंधन ढीले हुये हैं परंतु जाति व धर्म की राजनीति को व्यापक रूप से बढावा मिला हैं जिससे सांमप्रदायिक राजनीति को हवा मिलने लगी है।
- कुमार रवीश – बोलना ही है,लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, 2019 – प्रस्तुत पुस्तक में अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में विवेचन करते हुये उल्लेख किया हैं कि भारत में विभिन्न राजनीतिक प्रवक्ताओं के द्वारा किस प्रकार से सार्वजनिक मंच व मीडिया के माध्यम से सांमप्रदायिक राजनीति की भावनाओं को बढावा दिया जा रहा हैं। नफरत व असहिष्णुता को बहुत ही शातिर तरीके से जनता में फैलाने का प्रयास किया जा रहा हैं जो स्वस्थ लोकतंत्र को विफल कर रहें हैं।

शोध पत्र के उद्देश्य :–

उक्त शोध के निम्नांकित उद्देश्य अपेक्षित हैं –

1. भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक राजनीति के लिए उतरदायी कारणों को उजागर करना।
2. राजनीतिक दलों में संकीर्ण राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानना।
3. स्वस्थ लोकतंत्र में साम्प्रदायिकता किस स्तर तक बाधक है, ज्ञात करना।
4. धार्मिक सहिष्णुता एवं पारस्परिक सहयोग हेतु सुझाव तैलसना।
5. हिंसा व सांप्रदायिक मानसिकता के स्थान पर लोकतांत्रिक भावना का विकास करना।

परिकल्पना :–

प्रजातंत्र में शासन शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित होती हैं, क्योंकि लोतंत्र की बनियाद ही जनता पर टिकी हुई होती है। सफल जनतंत्र के लिए जनता का एक बहुत बड़ा भाग शासन संचालन में बिना किसी भेदभाव के सहभागी होना आवश्यक हैं। प्रतातंत्र जितना अधिक लोकप्रिय हुआ हैं उसी के अनुरूप इसके सन्मुख बाधाओं का भी विस्तार हुआ है। भारतीय लोकतंत्र जो कि विपरित परिस्थितियों में भी अपनी सफलता की कहानी ब्यान करता रहा हैं, तो वहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक सुचकांक सूची में पिछड़ने लगा है। राजनीति में नफरत और सांमप्रदायिकता को व्यापक स्तर पर बढावा मिलने के कारण भारतीय लोकतंत्र की साख को खतरा उत्पन्न होने लगा है। छल, कपट और विद्वेष के साथ राजनीतिक दलों के द्वारा वोटों का धार्मिक आधार पर धुव्रीकरण किया जाना सामान्य बात हो गई और विभिन्न घटनाओं को मजहबी रंग दे दिया जाता है। जिससे साम्प्रदायिक हिंसा व दुर्भावना को बल मिलने लगा हैं जो एक गम्भीर चुनौती बन चुकी है।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध पत्र का विषय भारतीय लोकतंत्र में साम्प्रदायिक राजनीति एक विश्लेषणात्मक अध्ययन के अन्तर्गत विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र भारत की राजनीति में मजहबी नफरत को सता प्राप्ति के लिए किस कदर बढावा दिया जा रहा है के सन्दर्भ में विश्लेषण किया गया है। शोध कार्य में तथ्यों एवं आंकड़ों के संग्रह में प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतों की अध्ययन में सहायक भूमिका रही है। प्राथमिक स्त्रोत के रूप में वैयक्तिक, साक्षात्कार व तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा सुचनाऐं संग्रह की गई हैं इसी प्रकार द्वितीयक स्त्रोत में विभिन्न शोध पत्रों, अनुसंधान कार्य, साहित्यक ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाऐं व इंटरनेट सहायक रहे है।

साम्प्रदायिकता का अभिप्राय :–

विशेषतया अपनी जाति, धर्म व सम्प्रदाय को अन्य से सर्वोच्च मानने, स्थापित करने व अपने हितों को किसी भी स्तर पर कानूनी या गैर–कानूनी तरीकों से संरक्षित करने की एक ऐसी संकीर्ण मनोवृति जो समाज व राष्ट्र को हिंसा व नफरत के बल पर खण्डित करने का प्रयास ही साम्प्रदायिकता कहलाती है। ''बहुसंस्कृतीय समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराहट वास्तव में विभिन्न समूहों के बीच चल रहे सता द्वन्द्व के लक्षण है। इस पारस्परिक द्वन्द्व को सैद्धान्तिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनीतिक विचारधाराके रूप में सम्प्रदायवाद का मूल सार है।''[3] प्रजातंत्र में जब धर्म, जाति व समूदाय को राजनीतिक दलों व साम्प्रदायिक हित समूहों के द्वारा विशेष महत्व दिया जाने लगता है तो ये साम्प्रदायिक राजनीति की शुरूवात हो जाती है, जो कि जनतंत्र की मुल भावना का ही अंत है।

स्वतंत्र भारत में साम्प्रदायिक राजनीति :–

भारतीय लोकतंत्र में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा व संस्कृति में व्यापक रूप से विविधता विद्यमान है। जो कि परस्पर सांमजस्य व सहिष्णुता के लिए चुनौती भरा कार्य है। भारत की आजादी भी एक साम्प्रदायिक विद्वेष से रंजित रही हैं, ब्रिटिश शासन काल में ही साम्प्रदायिक राजनीति का खेल यहाँ अग्रेजों ने खेलना शुरू कर दिया था, परिणाम के रूप उसी के परिणामस्वरूपं भारत का साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ। यद्यपि विभाजन के उपरांत भारतीय नेताओं ने शासन सता में मजहबी राजनीति को दरकिनार करने का विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जिसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली परंतु समय काल के अनुसार भारतीय राजनीति में संकीर्ण मनोवुति को बल मिला। पाकिस्तान प्रयोजित जिहादी आतंकी गतिविधियों ने साम्प्रदायिक जहर घोलने का काम किया तो वहीं देश के अन्दर भी विभिन्न धार्मिक समूहों को भी पनपने का अवसर मिलने लगा। विशेषकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े धर्मान्ध संगठनों ने अल्पसख्यक के रूप में अपने हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए धर्मान्धता फैलाना शुरू कर दिया। 1961 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बाद ये प्रचार किया गया कि मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा केवल ये लीग ही कर सकती है, इस प्रकार साम्प्रदायिक राजनीति को बल मिलने लगा। पाकिस्तानी दुष्प्रचार और सकीर्ण हिन्दुत्ववादी संगठनों ने भी आग में घी डालने का काम किया हैं विभिन्न अवसरों पर संकीर्ण मनोवृति के चंद धर्मान्ध लोगों के द्वारा जानबुझकर साम्प्रदायिकता को बढावा देने का प्रयास किया। धार्मिक संगठनों के द्वारा हिन्दू मुस्लिमों के बीच विवाह पर बवाल खड़ा करना, होली पर मुस्लिमों पर रगं फेंकना, मन्दिर मस्जिदों में तनाव पैदा करना आदि। साम्प्रदायिक राजनीति के बीज केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं हैं, अपितु हिन्दूओं में भी व्यापक रूप से स्वतंत्रता से पहले ही अंकुरित हो चुके थे। ''हिन्दू कट्टरता ने भी अलगाववाद की भावना को भड़कानें में अपनी भूमिका अदा की है। स्वतंत्रता से पूर्व भी यह भावना हिन्दूओं में विद्यमान थी कि विदेशी सिर्फ अंग्रेज नहीं हैं, बल्कि मुसलमान भी विदेशी हैं। हिन्दू महासभा, आर्य समाज तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में ....लेकिन इन संगठनों ने हिन्दू अतिवादिता को भी जन्म दिया।''[4] भारत में मजहबी राजनीति का सियासी फायदा उठाने का प्रयास जबसे राजनीतिक दलों के द्वारा खुलेआम किया जाने लगा तब से सम्पूर्ण देश में धार्मिक कट्टरता को राजनीतिक दांव पेच के रूप इस्तेमाल किया जाने लगा है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के द्वारा कट्टर हिन्दू बनने व धर्म के नाम पर मर मिटने का आह्वान, भारतीय जनता पार्टी की हिन्दूत्व की विचारधारा, अकाली दल की सिख समर्थन राजनीति, पीडीपी की मुस्लिम हितेषी राजनीति इस तरह के अनेकों राजनीतिक दल और संगठनों ने साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई है। कुंठित राजनीति ने देश को

[3] दीक्षित प्रभा – साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक सन्दर्भ, मेकमिलन, 1980 भूमिका
[4] चतुर्वेदी डॉ. गीता – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, 2015, पृ. 558

साम्प्रदायिक हिंसा में अनेक बार धकेला है जैसे 1963 कश्मीर में मस्जिद दगें, 1969 अहमदाबाद दगों में 1200 लागों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो वहीं 1974 में दिल्ली, 1978 अलीगढ दगें 1984 में इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण सिखों का नरसंहार, 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद, 2002 गुजरात, 2010 हैदराबाद, 2018 बिहार, 2020 दिल्ली व बैंगलोर, 2021 असम, 2022 कानपुर दगों ने देश को साम्प्रदायिक हिंसा में धकेलने का काम किया। इन सब के पिछे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राजनीतिक दलों व धार्मिक संगठनों की भूमिका रही है। हाल ही में दिल्ली में हुये दगों में बीजेपी नेता कपील मिश्रा का भड़काऊ भाषण को वजह बतायी जा रही हैं तथा इसमें पुलिस का रूख भी भेदभावपूर्ण सामने आया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो भारत में साम्प्रदायिक राजनीति में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है, आरएसएस व भाजपा के बढते वर्चस्व ने हिन्दूत्व के मूद्दे को बढा–चढाकर प्रचारित किये जाने कारण प्रशासनिक स्तम्भ को भी गहरा आघात लगा है। सता विरोधी आवाज को दबाने के लिए मजहबी हथियार को बेखोफ अपनाया जाने लगा है, जिससे भीड़ हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है। देश में कंही हिजाब को लेकर तो कंही नमाज को लेकर आजकल घटनाओं में वद्धि हुई हैं जबकि दूसरी तरफ कावड़ यात्रा पर प्रशासन द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है जो कि साम्प्रदायिक दृष्टि से एकपक्षीय रवैये को दर्शाती है। जातिगत दुर्भावनाओं में भी व्यापक रूप से वृद्धि हो रही है, दलितों पर अत्याचार व दुर्भाना के मामले बढ़ रहें है। राजस्थान में एक छात्र को मात्र पानी पीने की वजह से मार दिया जाता है तो वहीं यूपी में दलित युवती के साथ जघन्य अपराध होने के बाद रातोंरात प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निःसदेंह देश में जाति, धर्म व समुदायों के बीच पारस्परिक तनाव बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों के द्वारा बखुबी जातिगत व धार्मिक समीकरण के आधार पर निर्वाचन के दौरान अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाते हैं और चुनावी रैलियों में जाति व धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम आम बात हो गई है। जो कि साम्प्रदायिक लिहाज से भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया की छवी भी साम्प्रदायिक दुर्भावनाओं ग्रसित होती नजर आ रही हैं, मुलभूत मुद्दों की बजाय साम्प्रदायिक मुद्दों को प्राथमिकता से पूर्वाग्रही भावना के साथ उठाया जा रहा हैं और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को साम्प्रदायिक दुर्भावनाओं को भड़काने का खुला मंच प्रदान किया जा रहा है। साम्प्रदायिकता की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए निरंतर खतरे की ओर बढ रही है।

साम्प्रदायिक राजनीति पर नियन्त्रण हेतु सुझाव : –

मुख्य रूप से भारतीय लोकतंत्र में साम्प्रदायिक राजनीति पर अंकुश लगाने हेतु निम्न सुझाव अपेक्षित हैं –

- साम्प्रदायिक संगठनों व ताकतों पर कठोरता से शिंकजा कसा जाये।
- राजनीतिक दलों के द्वारा साम्प्रदायिक राजनीति करने पर दल की मान्यता रद्द की जाये।
- शिक्षा के स्तर में वृद्धि।
- धार्मिक संगठनों पर सरकारी नियंत्रण व विदेशी आर्थिक सहायता की जांच की जाये।
- साम्प्रदायिक सोहार्द को बढावा देने के लिए विभिन्न धार्मिक नेताओं को एक मंच पर लाया जाना चाहिए।
- जाति, धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर होने वाली हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये।
- अन्तर जाति व धार्मिक वैवाहिक संबधों को बढावा मिलना चाहिए।

निष्कर्ष :–

साम्प्रदायिक राजनीति किसी भी सभ्य देश के लिए लोकतांत्रिक मायने में एक कंलक हैं। धर्म एक आस्था का विषय है, इसे शासन व्यवस्था से जोड़ देना निहायत ही विकास का मार्ग अवरूद्ध और अंधविश्वास व भाग्यवाद की मानसिकता को बढ़ावा देना मात्र है। ''धर्म का प्रयोग राजनीति में जहाँ एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रभाव एवं शक्ति अर्जित करने के लिए धर्म को माध्यम बनाया जाता है। राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद जैसे धार्मिक विवाद का जिस प्रकार राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया है यह सर्वविदित है।''[5] भारत जैसे विशाल बहुसंस्कृति वाले लोकतंत्र में साम्प्रदायिक राजनीति का होना एक गम्भीर समस्या है। अगर राष्ट्र की तरक्की को दिशा देनी है, तो निश्चित रूप से यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना होगा। जाति व धर्म की राजनीति से उपर उठते हुये सहिष्णुता व पारस्परिक सहयोग को अहमियत देना बेहद जरूरी है। आज के दौर में धर्म के ठेकेदारों की हकीकत पहचानी जाये तो निश्चित रूप से ये लोग धर्म के नाम पर आम जनता को लुटने व भ्रमित कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के अलावा इनका देश व मनुष्य के विकास से कोइ लेना देना नहीं है। राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को निभाने में प्रायः असफल रहते हैं तो सबसे आसान रास्ता इनके लिए यही बचता है। क्योंकि जाति व धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करना सबसे आसान तरीका हैं बखुबी इस बात का फायदा उठाया जाता है। जिसका परिणाम विकास के मुद्दों को कोइ अहमियत नहीं मिल पाती है और देश साम्प्रदायिक हिंसा व परस्पर घृणा की घटिया राजनीति में पिछड़ने लगता है। वर्तमान दौर में भारतीय राजनीति का यही घिनोना सच सामने आ रहा है, निश्चित रूप से इस मसले पर भारतीय लोकतंत्र की साख को विश्व स्तर पर एक नकारात्मक छवि की दृष्टि से देखा जाने लगा है। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र को विश्व पटल पर एक आदर्श राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक दलों व धार्मिक संगठनों को संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना होगा तथा आम जनता को गम्भीर होकर जाति व धर्म से उपर उठते हुये ऐसे नेताओं व धर्म के दिखावटी ठेकेदरों राजनीति से बेदखल करना होगा तभी हम विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे और हमारे लोकतंत्र को मजबुती प्रदान की जा सकेगी।

■ ■ ■

[5] न्रवाल डॉ. प्रेमकुमार – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : संविधान निर्माण में भूमिका एवं राजनीतिक दर्शन, 2007 पृ.स. 111